

## भारत की संवृद्धि का वित्तपोषण- चुनौतियाँ और भावी दिशा\*

एस.एस. मूंदड़ा

श्री यदुवेन्द्र माथुर, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, भारत का निर्यात आयात बैंक: श्री सुनील श्रीवास्तव, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक: श्री आलोक श्रीराम, अध्यक्ष, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री (पीएचडीसीसीआई); श्री संजीव गुप्ता, अध्यक्ष, बैंकिंग समिति, पीएचडीसीसीआई; सम्मेलन के प्रतिनिधि; प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के सदस्य; देवियों और सज्जनों! मैं पीएचडी चेंबर का आभारी हूँ जिन्होंने 'भारत की संवृद्धि का वित्तपोषण- भावी दिशाएं' जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भाषण देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। पीएचडी चेंबर्स द्वारा उद्योग, व्यापार तथा उद्यम की उन्नति के लिए उनकी अनुसंधान - आधारित नीति परामर्शी भूमिका के जरिए किये गये प्रयास से मैं खुश हूँ। मुझे लगता है, आज का यह सम्मेलन इस यात्रा का महत्वपूर्ण कदम है। मैं यह भी समझता हूँ कि पीएचडी चेंबर और क्रिसिल ने भारत की संवृद्धि के वित्तपोषण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए ज्ञान रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठबंधन किया है और मैं उनके प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि उसमें की गई सिफारिशों का देश की आर्थिक वृद्धि और विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2. आज मैं अपने भाषण में भारत की संवृद्धि की संभावना, भारत की वृद्धि के लिए समुचित मॉडल, संभावित वृद्धि दर प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों तथा इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए भावी दिशा के संबंध में कहना चाहता हूँ। तथापि, मैं वैश्विक आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण

\* पीएचडीसीसीआई द्वारा 9 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में आयोजित "भारत की संवृद्धि का वित्तपोषण - भावी दिशा " पर आयोजित सम्मेलन में श्री एस.एस.मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये भाषण का मुख्य अंश

प्रस्तुत करते हुए भारत की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए अपने भाषण की शुरुआत करता हूँ।

### वैश्विक विहंगावलोकन

3. इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में चार मुख्य विषय हैं- चीन की मंदी, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा वर्तमान दर में वृद्धि, पण्य, विशेष रूप से तेल के वैश्विक मूल्यों में भारी गिरावट तथा आर्थिक बहाली में लगातार मंदी की स्थिति। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईईज) को देखने से पता चलता है कि 2015 के दौरान जापान में वृद्धि 0.8 प्रतिशत पर वस्तुतः स्थिर रही जबकि महाद्वीपीय यूरोप द्वारा मात्र 1.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद की जाती है। 2015 के दौरान उत्तरी अमरीका सहित यूएसए की बहाली मामूली है और यूके द्वारा 2.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज करने की संभावना है।

4. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीईज) की वृद्धि में भी काफी मंदी देखी जा रही है। मंदी के दबाव को देखते हुए चीन की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से घटकर 6.8 प्रतिशत होने की संभावना है, जब कि रूस (0.6 प्रतिशत से -3.4 प्रतिशत) तथा ब्राजील (-1.5 प्रतिशत से- 0.1 प्रतिशत) की वृद्धि दरें ऋणात्मक होने की संभावना है। अन्य ब्रिक्स देशों में, दक्षिण अफ्रिका की अनुमानित वृद्धि 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.1 प्रतिशत होने की संभावना है। इस प्रकार व्यापक आर्थिक महाशक्तियों और प्रमुख ईएमडीई की ऋणात्मक से सकारात्मक वृद्धि दरों की पृष्ठभूमि में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रही है और उसमें और अधिक वृद्धि करने की क्षमता है। भारत में संवृद्धि की संभावना धीरे-धीरे बेहतर ही रही है। कारोबार का विश्वास दृढ़ बना हुआ है और जैसे केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल के परिणाम प्राप्त होने लगे हैं, इससे यह अपेक्षा की जाती है कि निजी निवेश और ग्राहक विश्वास को पुनर्जीवन मिलेगा। हमारा दृढ़ विश्वास है कि उच्च वृद्धि पथ सुनिश्चित करने एवं बनाए रखने के लिए सामान्य मुद्रास्फीति का होना अत्यावश्यक है। इससे यह प्रश्न उभरकर आता है कि " **हमारी संवृद्धि की संभावना क्या है?**"

## भारत की संवृद्धि की संभावना

5. यह प्रश्न शैक्षणिक और नीति अनुसंधान क्षेत्र में सक्रिय वाद-विवाद का विषय बना हुआ है। देश की संभाव्य संवृद्धि दर के संबंध में साहित्य /अनुसंधान पत्रों में विभिन्न अनुमान लगाए गए हैं। संवृद्धि की संभावना के अनुमान के संबंध में प्रणाली संबंधी मुद्दों के बावजूद फिर भी, एक उचित सीमा तक सर्वसम्मति है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में अपनी संभाव्य वृद्धि से भी कम दर पर वृद्धि कर रही है और इस ऋणात्मक आउटपुट गैप (अर्थात् संभाव्य वृद्धि में से वास्तविक वृद्धि को घटाकर) को कम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

6. वह क्या है जो भारत को उसकी संभाव्य उच्चतर वृद्धि दर प्राप्त करने से रोक रहा है? चूंकि आज के सम्मेलन का विषय है "भारत की संवृद्धि का वित्त पोषण - भावी दिशाएं" मैं कुछ बुनियादी सवालों के साथ यह विषय आरंभ करना चाहता हूँ : **क्या वित्त की उपलब्धता वृद्धि को रोक रही है?** वित्त क्षेत्र को चाहिए कि वह वास्तविक अर्थव्यवस्था की जरूरतों में सहायक बने न कि स्वयं वृद्धि को संचालित करे। हमने वैश्विक आर्थिक संकट के रूप में वास्तविक अर्थव्यवस्था के सामने वित्तीय अर्थव्यवस्था के खतरे देखे हैं। मेरा तर्क है कि वित्त की उपलब्धता, अब तक, एक अत्यन्त ही लघु समस्या रही है और संरचनात्मक समस्याओं के कारण ही वृद्धि दर अपने संभावित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। यहां पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ल्ड बैंक की 'डूइंग बिजनेस 2015' रिपोर्ट के अनुसार समग्र रैंकिंग में हमने एक देश के रूप में 189 देशों में से 142 रैंक प्राप्त किया है, जबकि, सरलता से 'ऋण प्राप्त करना' मापदंड की दृष्टि से हमने तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 36 वां स्थान प्राप्त किया है।

7. जैसा कि हम भारत की संवृद्धि के वित्तपोषण के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, अब मैं और अधिक प्रकाश डालने हेतु कतिपय उचित बिंदुओं को प्रस्तुत करता हूँ और इस विषय के साथ अपनी बात शुरु करता हूँ कि हमारा संवृद्धि मॉडल क्या होने चाहिए।

## हम किस प्रकार की वृद्धि पाना चाहते हैं?

8. हमारा संवृद्धि मॉडल कैसा होना चाहिए, यह भी नीति निर्माताओं में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या वह विनिर्माण संचालित, निर्यात-आधारित संवृद्धि होना चाहिए, क्या वह अवसंरचना आधारित संवृद्धि या घरेलू खपत द्वारा संचालित होना चाहिए? वास्तव में, सभी मॉडल की अपनी-अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं। हमारे सामने चीन की वर्तमान मंदी एवं 90 के दशक के अंत में एशियाई आर्थिक संकट के उदाहरण हैं, जो अंशतः अवसंरचना निर्माण में भारी निवेश जो एक बिंदु के बाद सकारात्मक प्रतिलाभ नहीं देता या निर्यात-आधारित संवृद्धि पर अत्यधिक निर्भरता का परिणाम है। संभवतः, हमें निम्नलिखित सभी के उचित मिश्रण की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे- घरेलू खपत में बढ़ोतरी, अवसंरचना एवं विनिर्माण में निवेश पर आधारित संवृद्धि। मुझे विश्वास है कि हम सभी उस दौर से काफी आगे गुजर चुके हैं जब हम संवृद्धि को संचालित करने के लिए विश्व विनिर्माण हब बनने पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर सकते थे। मेरे विचार से, हम ऐसे संवृद्धि मॉडल की कामना करने में सफल होंगे जो प्रधान रूप से घरेलू विनिर्माण एवं वैश्विक सेवा वितरण पर केंद्रित हो, और जो लंबे समय तक चल सकने वाला हो। यह अहसास होना भी आवश्यक है कि वृद्धि केवल तभी चिरस्थायी हो सकती है जब उसमें प्रकृति और संभावना का समावेश हो। क्षेत्रों, समुदायों आदि के बीच विकास में परस्पर असमानताएं या विषमताएं समाज के लिए न तो वांछित हैं और न ही अच्छी हैं।

## संवृद्धि के मार्ग में मुख्य चुनौतियाँ

9. हमने भारत की संभाव्य वृद्धि दर एवं हमें किस प्रकार का वृद्धि मॉडल चाहिए इस संबंध में चर्चा कर लिया है, अब मैं संभाव्य वृद्धि दर प्राप्त करने के मार्ग में आनेवाली कतिपय मुख्य चुनौतियों पर प्रकाश डालता हूँ। यद्यपि धीमी वृद्धि के कतिपय सामाजिक-राजनीतिक कारण भी हैं। मेरे विचार से आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ

प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:

ए: भौतिक तथा वित्तीय दोनों में अवसंरचना में निवेश में कमी।

बी: वित्तीय वंचन का उच्च स्तर।

सी: कौशल में कमी का रोजगार प्राप्ति में निहितार्थ है।

डी: सकल पूंजी निर्माण में गिरावट और घटती घरेलू बचत दर।

### क्या करने की आवश्यकता है?

10. सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक इन चुनौतियों से सचेत हैं और इन पर दीर्घकालिक रूप से काबू पाने के लिए उपाय करते आ रहे हैं। यहां पर इस बात पर जोर देना भी उचित होगा कि 'पूंजी प्रधान' तथा 'श्रम प्रधान' कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने के बीच एक स्पष्ट संतुलन स्थापित करने की जरूरत है, चाहे उद्योग हो या सेवा क्षेत्र में। देश में विशुद्ध संख्या में शिक्षित कार्यबल को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है। समय को साथ-साथ हमने देखा है कि सेवा क्षेत्र का योगदान पर्याप्त रूप से बढ़कर जीडीपी का लगभग 57 प्रतिशत हो गया है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में हाल की वृद्धि का प्रमुख कारण है सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं आईटी समर्थित सेवा (आईटीईएस) क्षेत्रों, ई-कॉमर्स एवं व्यावसायिक सेवा क्षेत्रों जैसी क्षमता प्रधान सेवाओं का तेजी से विकास, जो प्रायः बाह्य बाजार से अभिप्रेरित हैं। इस सेवा-क्षेत्र की वृद्धि की गुणवत्ता और स्थिरता के साथ-साथ उसकी भावी वृद्धि की संभाव्यता के संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं। तथापि, मेरा विश्वास है कि सरकार ने डिजिटल भारत और क्षमता विकास के लिए जो प्रेरणा दी है उससे दोनों के विस्तार में सहयोग प्राप्त होगा जिसमें आधुनिक सेवाएं जैसे ई-कॉमर्स, संचार एवं वित्त और साथ ही अन्य पारंपरिक सेवाएं जैसे व्यापार, परिवहन तथा भंडारण आदि शामिल हैं।

### शहरों की ओर पलायन

11. लोगों का शहरी क्षेत्रों की ओर सतत प्रवसन से वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इससे आवास, परिवहन, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुविधा इत्यादि की मांग बढ़ेगी। सरकार/ नगरपालिका निकायों को सड़कें, सीवेज प्रणाली, जल आपूर्ति सुविधाओं इत्यादि में निवेश करने की भी जरूरत है। शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होते हुए भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाना जारी रहेगा क्योंकि 60 प्रतिशत से अधिक लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन करते हैं।

### ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना

12. ग्रामीण क्षेत्रों की आय के स्तर को भूमि सुधार, जैसे खंडित जमीनों का समेकन, जो आधुनिक फसल कटाई पद्धतियों में मदद कर सकता है और ग्रामीण जनता को कृषि से इतर कार्यकलापों हेतु प्रशिक्षित करने के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। ऋण अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों को वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने एवं कुशल फसल बीमा ढांचे के जरिए अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए।

13. भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत पहले से अपनी नीतियों जैसे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी मानदंड, समाज के कमजोर वर्गों को उधार देना, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण तथा हाल के वित्तीय समावेशन अभियान के जरिए समावेशी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है, जो इन दर्शकों को भली-भांति ज्ञात है। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केंद्रों में शाखा के विस्तार की रिजर्व बैंक की नीतियां भी इस पहल का एक अंश है। बचत को सही रास्ता प्रदान करने एवं उसे लाभप्रद आस्ति निर्माण में लगाने के इन प्रयासों का लाभ उठाने की अब आवश्यकता है। दो नव लाइसेंसधारी पूर्ण-सेवा बैंक, ग्यारह भुगतान बैंक एवं निकट भविष्य में लाइसेंस प्राप्त करने वाले लघु वित्त बैंकों से वित्त की उपलब्धता को और बल मिलेगा तथा ऋण मध्यस्थता

प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होगी और इस प्रकार यह स्थायी और समावेशी वृद्धि में सहयोग प्रदान करेगा।

### एसएमई वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना - भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक

14. जब हम समावेशी वृद्धि की बात करते हैं तो यह उचित होगा कि हम एमएसएमई क्षेत्र पर बात करें जिसमें स्थानीय मांग को बढ़ाने तथा खपत को संचालित करने के जरिए दृढ़ वृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता है। वर्तमान में, देश के जीडीपी में एमएसएमई का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा, विनिर्माण उत्पाद में 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत हिस्सा है। वे कृषि के बाद रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराते हैं और उद्यमिता तथा नवोन्मेषण के लिए नर्सरीज के रूप में कार्य करते हैं। आर्थिक वृद्धि में इस क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए उपाय करते आ रहे हैं। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अपनी ओर से कई पहल की हैं। एमएसएमई क्षेत्र के विलंबित भुगतान के मामले का विशेष रूप से समाधान खोजने के लिए एक प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के रूप में टीआरईडीएस की संकल्पना की गई है ताकि एमएसएमई के बीजकों/ विनिमय बिल को भुनाया जा सके। दूसरी तरफ, बैंकों में एमएसएमई प्रभागों के क्षमता निर्माण के अंश के रूप में तथा उद्यम-संवेदनशीलता विकसित करने के लिए रिजर्व बैंक ने हाल में वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारियों के लिए योजनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भारत सरकार ने भी हाल में एमएसएमई उद्यमों की बहाली और पुनरुद्धार के लिए रूपरेखा निर्धारित की है। भारत सरकार की अन्य पहलों जैसे, 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया मिशन' एवं 'डिजिटल इंडिया' से भी इस क्षेत्र को स्पष्ट तौर पर और अधिक बल मिलता है।

### संवृद्धि के वित्तपोषण में बैंकों की भूमिका

15. परंपरागत रूप से, अन्य उभरते बाजारों की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बैंकों की प्रमुख भूमिका रही है। बैंक ऋण के प्रमुख स्रोत रहे हैं, चाहे वह कॉर्पोरेट के प्रॉजेक्ट के विकास के

लिए हो या कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों के लिए। यद्यपि, यह माना जाता है कि बैंकों का प्रमुख कार्य परिपक्वता एवं चलनिधि रूपांतरण है, लेकिन बैंक बहियों में आस्ति-देयता असंतुलन की सीमा की भी एक सीमा है। बैंकों की अवसंरचना पोर्टफोलियो में बहुमात्रा में पाए गए संकट से इस प्रकार के प्रॉजेक्ट का गंभीरतापूर्वक मूल्यांकन करने की उनकी क्षमता का मामला भी सामने आता है। परिपक्व बाजारों में बैंकों की विशिष्ट भूमिका है ऋण की मांग पैदा करना और उसके बाद बाजार में इच्छुक लोगों को उपलब्ध करना। बैंक प्रमुख रूप से कार्यशील पूंजी वित्त का कार्य करता है और अपने ग्राहकों को संरचित वित्तीय समाधान प्रदान करता है। बैंक विभिन्न वित्त क्षेत्र उत्पादों के बाजार निर्माता के रूप में भी कार्य करता है। हमारे वित्त बाजारों के क्रमिक विस्तार और सघनता के साथ, बैंकों ये यह अपेक्षा किया जाना उचित होगा कि वे धीरे-धीरे अपना ध्यान एसएमई एवं खुदरा ग्राहकों पर केंद्रित करना शुरू कर दें जबकि दीर्घावधि संसाधन जुटाने का कार्य अन्य खिलाड़ियों के लिए छोड़ दें, जैसे, पेंशन फंड/ बीमा कंपनी, जिसकी वजह से बैंकों के तुलन पत्रों में लंबे समय तक देयताएं बनी रहती हैं।

16. इस परिप्रेक्ष्य से एक और कारक जुड़ा हुआ है। बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता उनकी पूंजी की स्थिति पर निर्भर करती है जो निधि प्रदान किए जाने वाले प्रॉजेक्ट की व्यवहार्यता से मार्गदर्शित है। हाल के दिनों में सीमित बैंक ऋण वृद्धि के कारणों में से एक है वित्तीय आस्तियों में तनाव के परिणामस्वरूप जोखिम से बचाव।

### क्या उधारकर्ता अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं?

17. मैंने बहुत से अवसरों पर उधारकर्ताओं के दायित्वों का मुद्दा उठाया है और उसे फिर से दोहराते हुए मैं एक बार फिर उन मुद्दों पर जोर देना चाहूंगा। वृद्धि की खोज को तो समझा जा सकता है लेकिन उधारकर्ता उस वृद्धि के वित्तपोषण के लिए अपने निजी धन को लगाए बिना बैंक निधि पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रह सकता।

दि लैबरिन्थिन मेज जिसके जरिए अनेकों बड़े अवसंरचना प्रॉजेक्ट का वित्तपोषण कराया गया है, अत्यंत निम्न या नगण्य स्तर के इक्विटी योगदान की ओर संकेत करता है जिसके परिणामस्वरूप अत्यंत उच्च स्तर का लाभ प्राप्त होता है और प्रवर्तकों को इसमें वस्तुतः कोई लाभ नहीं होता। यहां पर ऐसा ही एक प्रतिरूप दिखाई देता है। गत कुछ वर्षों में हुई वृद्धि का प्रमुख कारण इन्फ्रा प्रॉजेक्ट था। ये प्रॉजेक्ट कम इक्विटी वाले थोड़े से प्रवर्तकों द्वारा लागू किए गए थे जिसका हवाला मैंने पहले दिया था। मुझे लगता है कि इस छोटे से समूह के पास इतनी इक्विटी भी नहीं है कि वे रुके प्रॉजेक्ट की बहाली के लिए उचित हिस्से का योगदान कर सकें, यहां पर नए प्रॉजेक्ट के प्रवर्तन की बात नहीं करेंगे। तो यह बात सभी को स्पष्ट होनी चाहिए कि गति को बनाए रखने के लिए वे या तो अपने बल पर नई इक्विटी जुटाए या दूसरों के लिए रास्ता छोड़े जो वर्तमान एवं नए प्रॉजेक्ट दोनों के लिए इस प्रकार की इक्विटी का योगदान कर सकता है।

18. यहाँ पर यह कहना भी उचित है कि वर्तमान विधि प्रणाली में अलाभकारी फर्मों को आसानी से बंद/टेकओवर करने की सुविधा नहीं है। ऐसी समस्याओं पर काबू पाने के लिए एवं तनावग्रस्त फर्मों के महत्व को बचाने के लिए, यह अत्यावश्यक है कि जल्द एक दिवालियापन कोड लागू करने के उपाय किए जाएं। तनावग्रस्त वित्तीय फर्मों के समाधान के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के निर्माण का कार्य भी जल्द पूरा करने की आवश्यकता है।

19. कॉरपोरेट के संचित ऋण की बहुलता का कारण है निम्न-लागत वाले, प्रचुर एवं लचीले ऋण की उपलब्धता, जिसे अमरीका, यूके, यूरो क्षेत्र एवं जापान में किए गए असाधारण नीतिगत उपायों द्वारा प्रस्तुत सर्च-फॉर-यिल्ड वाले वातावरण ने सुसाध्य बनाया। बहुत से कॉरपोरेट ने विदेशी एवं घरेलू, दोनों मुद्राएं उधार लेकर लाभ में वृद्धि की। एक कॉरपोरेट होने के नाते आपको वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। बाजारों की अंतरसंबद्धता उसे अस्थिरता में डालती है।

ऐसी संस्थाएं जिन्होंने विदेशी मुद्रा में भारी मात्रा में लिए गए उधार के लिए कोई बचाव व्यवस्था नहीं की हैं उन्हें अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।

### गवर्नेंस में सुधार

20. भारत को वृद्धि के लिए बाह्य पूंजी की सतत रूप से आवश्यकता होगी और इसलिए हमें निवेशक विश्वास को बढ़ावा देने के लिए अवश्य अनुकूल माहौल बनाना है, जिसमें अन्य के साथ-साथ स्थिर, प्रभावशाली एवं पूर्वानुमेय विधि, कराधान तथा लेखापरीक्षा ढांचे के साथ विश्वसनीय क्रेडिट रेटिंग व्यवस्था शामिल हैं।

### निष्कर्ष

21. मैंने पहले जिन कतिपय बिंदुओं पर प्रकाश डाला था उसे दोहराते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। हाल के दिनों में मामूली वृद्धि का एक अत्यंत प्रमुख कारण लाभप्रद प्रयोजनार्थ वित्त की उपलब्धता के बजाय वैश्विक एवं घरेलू बाजारों में लगातार कमजोर आर्थिक स्थिति का बना रहना है। आगे भी, वैश्विक निवेशक समुदाय के लिए निवेश हेतु एक प्रमुख गंतव्य-स्थान के रूप में भारत के आकर्षण को देखते हुए वित्त की उपलब्धता बाधक नहीं होनी चाहिए। तथापि, संभावित उच्चतर एवं स्थिर वृद्धि अनिवार्य रूप से उच्चतर बचत एवं अवसंरचना में निवेश के जरिए ही संभव है जिसके लिए समष्टिआर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता माहौल के कुशल सहयोग की जरूरत है। इसलिए, यह आवश्यक है कि क्रमिक आर्थिक सुधार की गति को बनाया रखा जाए जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था। भारतीय रिजर्व बैंक एवं सरकार दोनों को वृद्धि के लिए आवश्यक समर्थक भूमिका का निर्वाह करने की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करना होगा, जैसे, सामान्य मुद्रास्फीति, स्थिर विनिमय दर, राजकोषीय समेकन, पूर्वानुमेय विधि/ कराधान एवं लेखापरीक्षा व्यवस्था। भूमि अधिग्रहण के संबंध में होने वाली कठिनाइयों का जल्द समाधान, जीएसटी एवं

दिवालियापन कोड के संबंध में कानून लागू करने से देश में निवेश का माहौल सुदृढ़ होगा और वृद्धि को गति मिलेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता की

गति को सुदृढ़ करना, अधिक प्रभावशाली एवं बेहतर-निर्देशित लोक व्यय, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) तथा दक्षता विकास, समान रूप से महत्वपूर्ण कदम होगा।

धन्यवाद !